

1 जून से देश के 6 राज्यों में इंटर-स्टेट ई-वे बलि लागू

चर्चा में क्यों ?

जीएसटी परिषद के फैसले के क्रम में वस्तुओं की अंतर-राज्यीय ढुलाई के लिये ई-वे बलि प्रणाली को 1 अप्रैल, 2018 को लागू कर दिया गया। ई-वे बलि, जी.एस.टी. के तहत एक बलि प्रणाली है जो वस्तुओं के हस्तांतरण की स्थिति में जारी की जाती है। इसमें हस्तांतरण की जाने वाली वस्तुओं का विवरण तथा उस पर लगने वाले जी.एस.टी. की पूरी जानकारी होती है।

- नियम के अनुसार, ₹50,000 से अधिक मूल्य की वस्तु, जिसका हस्तांतरण 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक किया जाना है, पर इसे आरोपित करना आवश्यक होगा।
- जनता की सुविधा के लिये लक्विडि पेट्रोलियम, गैस, खाद्य वस्तुओं, गहने इत्यादि 150 उत्पादों को इससे मुक्त रखा गया है।
- वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, इसे फरवरी 2018 तक अंतर-राज्य स्तर (inter-state level) पर तथा जून 2018 तक अंतरा-राज्य स्तर (intra state level) पर लागू करना आवश्यक है।

कनि-कनि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू?

- 30 मई, 2018 तक आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, राजस्थान, सिककिम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लागू किया जा चुका है।
- इसके साथ-साथ केंद्रशासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी में राज्यों के भीतर सामान की ढुलाई के लिये इंटर-स्टेट ई-वे बलि प्रणाली लागू कर दी गई है।
- अब ई-वे बलि सफलतापूर्वक तैयार किये जा रहे हैं और 30 मई, 2018 तक 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा ई-वे बलि जारी हो चुके हैं, जिनमें 2 करोड़ इंटर-स्टेट ई-वे बलि भी शामिल हैं।
- पी.आई.बी. द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार नमिनलखित राज्यों में इंटर-स्टेट ई-वे बलि लागू किये जा रहा है-

क्रम संख्या	राज्य	लागू होने की तारीख
1.	छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू-कश्मीर, मजिोरम, ओडिशा और पंजाब	01 जून, 2018
2.	तमलिनाडु	02 जून, 2018
3.	पश्चिम बंगाल	03 जून, 2018

- ई-वे बलि प्रणाली को लागू हुए दो महीने हो चुके हैं और फलिहाल यह बना किसी कठिनाई के सुगमता से काम कर रही है।
- प्रतिदिन औसतन 12 लाख से ज्यादा ई-वे बलि जारी हो रहे हैं।

ई-वे बलि प्रणाली की उपयोगिता

- इससे कर योग्य वस्तु पर नगिरानी रखना आसान होगा तथा कर चोरी में कमी आएगी।
- ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व वैट के तहत भी वस्तुओं के अंतर-राज्य हस्तांतरण पर कर एवं बलि के प्रावधान थे। इस बलि के जारी होने से अंतरा-राज्य स्तर पर भी इसका वस्तितार होगा।
- इससे संपूर्ण भारत में जी.एस.टी. के निर्धारण में एकरूपता आएगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
- सरकार का कर संग्रहण बढ़ेगा और उसका प्रयोग सामाजिक आर्थिक समावेशन में होगा।
- वस्तुओं की आवाजाही का रिकॉर्ड रखने से उनके लिये उत्तरदायित्व तय किये जा सकेंगे, इससे अन्य अपराधों में भी कमी आ सकती है।

